अंदेशा | मझौली बाईपास पर बंद स्ट्रीट लाइट से बढ़ रहे हादसे

राहगीरों के लिए एनएच-30 बना खतरे का सफर

सिहोरा, नवभारत। नेशनल हाईवे-30 पर स्थित मझौली बाईपास इन दिनों गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और एनएचएआई की बेरुखी का शिकार बना हुआ है। यहां लगी स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिसके कारण रात होते ही पूरा इलाका गहरे अंधेरे के आगोश में समा जाता है। आलम यह है कि यह महत्वपूर्ण बाईपास अब 'ब्लैक स्पॉट' में तब्दील हो चुका है, जहां रोजाना वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।

अंधेरे में काल बनकर दौड़ रहे वाहन

जानकारी के अनुसार सूरज ढलते ही मझौली बाईपास पर विजिबिलिटी (दृश्यता) पूरी तरह शून्य हो जाती है। हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ते भारी वाहन, अचानक सामने आ जाने वाले मवेशी और सड़क किनारे बिना किसी इंडिकेटर या सूचक के खड़े ट्रक इस घने अंधेरे में दिखाई नहीं देते, जिससे आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इस तरह की लापरवाही के कारण पूर्व में कई गंभीर सड़क हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन सिहोरा का जिम्मेदार अमला इससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है।

प्रशासन को शायद बड़े हादसे का इंतजार

हाईवे की इस बदहाली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह बेपरवाह हो चुका है और स्थानीय प्रशासन को शायद किसी बड़े और दर्दनाक हादसे का इंतजार है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। जिम्मेदार अधिकारियों का यह अड़ियल रवैया साफ दर्शाता है कि उन्हें जनता की जान-माल की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

जनआक्रोश के कारण आंदोलन की सुगबुगाहट

क्षेत्रीय नागरिकों और वाहन चालकों ने इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही थमा दिए गए। धरातल पर अब तक एक भी लाइट को सुधारा नहीं जा सका है। प्रशासन के इस टालमटोल रवैये से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पनप रहा है और अब नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे चक्काजाम और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

जिम्मेदारी मढ़ने का खेल, तालमेल के अभाव में जनता परेशान

बताया जाता है कि यह हाईवे तकनीकी रूप से एनएचएआई के अधीन आता है, लेकिन लाइटिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय विद्युत विभाग व प्रशासनिक एजेंसियों के समन्वय से तय होती है। इसी तकनीकी घालमेल का फायदा उठाकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर मढ़ने में व्यस्त हैं। विभागों के बीच आपसी तालमेल और इच्छाशक्ति के इसी अभाव का खामियाजा भुगतते हुए स्थानीय जनता और राहगीर हर रात मौत के साए में सफर कर रहे हैं।

तत्काल सुधार और सुरक्षा ऑडिट है समय की मांग

मझौली बाईपास को सुरक्षित बनाने के लिए अब केवल पैचवर्क नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नागरिकों की पुरजोर मांग है कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को युद्धस्तर पर तुरंत चालू किया जाए, पूरे बाईपास का सुरक्षा ऑडिट हो, और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चमकीले रिफ्लेक्टर व चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। इसके साथ ही, रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों पर नकेल कसी जा सके।

बरेला में धूमधाम से मनाई गई ईद-उल-अज़हा

नवभारत, बरेला। बरेला में ईद-उल-अजहा बड़े ही हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर जामा मस्जिद, बरेला में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर ईद की विशेष नमाज अदा की।

नमाज के बाद सभी ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और समाज में प्रेम व सौहार्द का संदेश दिया। नगर में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरा त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

देश में खुशहाली के लिए विशेष नमाज

जामा मस्जिद में आयोजित विशेष जमात के दौरान मौलाना अरमान रजा ने नमाज अदा कराई। नमाज संपन्न होने के बाद उन्होंने दुआ मांगी, जिसमें देश में अमन-चैन, स्थायी खुशहाली एवं आपसी भाईचारे की कामना की गई। इस दौरान बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा बरेला क्षेत्र आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरा। इस मौके पर समाज के अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष शानू रेहान अली, शेख सलीम, शेख सद्दाम, अहमद खान, सत्तार खान, गफ्फार खान, शाहिद खान, शाकिर खान, शेख अब्बास, शेख नवाब, सलीम ठेकेदार, शेख साजिद, शेख वाहिद, निसार खान, शाहरुख खान, शेख सुलेमान, शेख समीर, मुश्ताक खान, पप्पू खान, मोहसिन खान, राजू खान, जाहिद, सिकंदर खान, फारुख खान, सोनू खान, टिन्नी शाह, साबू शाह, शेख कलीम और शेख नईम सहित कई लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

जमीन सूखी, पर सरकारी कागजों में तैर रहा है जल गंगा अभियान!

मझौली नगर परिषद का अजब कारनामा, बूंद-बूंद पानी को तरस रही जनता, अफसरों में सिर्फ फोटो खिंचवाने की होड़

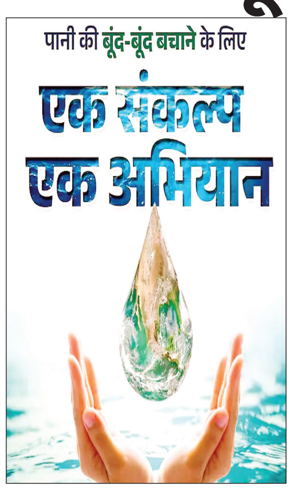

मझौली, नवभारत संवाददाता, जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए पूरे प्रदेश में बड़े जोर-शोर से 'जल गंगा अभियान' चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जबलपुर जिले की मझौली नगर परिषद में इन दिनों एक अलग ही अनोखा अभियान चल रहा है।

चौंकिए मत! यह अभियान जमीन पर नहीं, बल्कि सिर्फ सरकारी फाइलों, वातानुकूलित कमरों और सोशल मीडिया के पन्नों पर सरपट दौड़ रहा है। धरातल पर स्थिति यह है कि नगर के वार्डों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है, लेकिन परिषद के जिम्मेदार कागजी विकास की 'गंगा' बहाने में व्यस्त हैं।

फाइलों में सिमटे जल संरक्षण के पुख्ता इंतजाम

नियमों और निर्देशों के मुताबिक, इस अभियान के तहत नगर परिषद क्षेत्र के पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों की साफ-सफाई और जलस्तर सुधारने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने थे। लेकिन मझौली में इस योजना की जमीनी हकीकत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। धरातल पर न तो प्राचीन जलस्रोतों की सुध ली जा रही है और न ही आने वाले मानसून को देखते हुए वॉटर हार्वेस्टिंग या जल संरक्षण का कोई ठोस खाका नजर आ रहा है। नगर परिषद के रसूखदार सिर्फ बैठकों का दौर चलाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

पानी को तरस रही जनता, अफसर एसी कमरों में मस्त

पारा आसमान छू रहा है और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। नगर के कई वार्डों में लोग सुबह से ही पानी के इंतजाम के लिए भटकने को मजबूर हैं। बूंद-बूंद पानी के लिए तरसती जनता जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है, तो उन्हें ढांढस बांधने के अलावा कुछ नहीं मिलता। विडंबना देखिए कि एक तरफ जनता सड़क पर पानी के लिए संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ नगर परिषद के नुमाइंदे ठंडे एसी कमरों में बैठकर 'जल संरक्षण' की खोखली रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर चल रहा वाहवाही लूटने का खेल

सूत्रों और स्थानीय नागरिकों की मानें तो इस तथाकथित 'जल गंगा अभियान' का असली मकसद जल संरक्षण नहीं, बल्कि केवल 'फोटोबाजी' बनकर रह गया है। अभियान के नाम पर अधिकारी और चुनिंदा जनप्रतिनिधि सूखी पड़ी जगहों पर फावड़ा थामकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, और फिर उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार की नजरों में अपना नंबर बनाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। जमीन पर एक बूंद पानी सहेजने का काम नहीं हुआ, लेकिन कागजों में लाखों के खर्च और सफलता की कहानियां लिखी जा रही हैं। जिसको लेकर जनता के मन में यह प्रश्न उठा रहा है कि क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाले 'लाइक' और 'कमेंट्स' से मझौली की प्यासी जनता का गला तर हो जाएगा? या फिर सरकारी बजट को ठिकाने लगाने के लिए इस अभियान को 'कवच' बनाया जा रहा है?

जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कब रुकेगी

यह स्थिति साफ इशारा करती है कि मझौली नगर परिषद के लिए जनहित के मुद्दे सिर्फ एक औपचारिकता मात्र हैं। जब तक योजनाएं फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर नहीं आएंगी, तब तक मझौली का जल संकट दूर होना नामुमकिन है। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले सरकारी बजट का यह तमाशा अब बंद होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस 'कागजी जल गंगा अभियान' पर जबलपुर जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग संज्ञान लेता है या फिर मझौली की जनता इसी तरह कागजी विकास के बीच असली प्यास से तड़पती रहेगी।

श्री सिद्ध महाकाली पीठ में आज से बहेगी श्रीकृष्ण कथा की ज्ञान गंगा

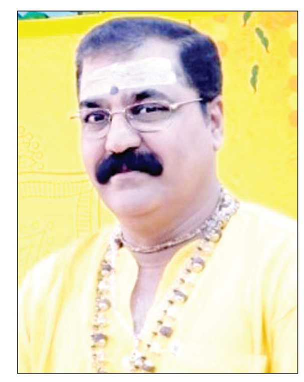

नवभारत, जबलपुर। पाटन रोड रैगवां स्थित श्री सिद्ध महाकाली पीठ मंदिर, सुधा सागर बिहार में शुक्रवार से संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। कथा का वाचन कथाव्यास आचार्य पं. सुधीर दुबे शास्त्री (बबलू महाराज) द्वारा प्रतिदिन शाम 5 से रात 8 बजे तक किया जाएगा।

कथा की शुरुआत शुक्रवार को कलश शोभायात्रा, बैठकी व महात्म्य कथा के साथ होगी। इसके बाद क्रमशः राजा परीक्षित जन्म (30 मई), प्रहलाद चरित्र (31 मई), समुद्र मंथन व श्रीकृष्ण जन्मोत्सव (1 जून), नंद उत्सव व गोवर्धन पूजन (2 जून), और श्रीकृष्ण-रुक्मणी विवाह (3 जून) प्रसंग मनाए जाएंगे। कथा विश्राम 04 जून को सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष के साथ होगी। 5 जून शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से हवन व भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में पाटन सहित आसपास के बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है।

ईंधन बचाने निकाली साईकिल यात्रा

नवभारत, बेलखाडू। विनायक राव की जयंती पर जबलपुर संस्कार सिटी सूरतलाई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की प्रभात शाखा संस्कार तरुण व्यवसायिक शाखा स्वयं सेवकों को द्वारा साइकिल ट्रिप का आयोजन किया गया।

साइकिल ट्रिप संस्कार सिटी सूरतलाई के विभिन्न अंचलों से गुजरती हुई माल बाबा खैरी के दरबार में पहुंची वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टर महेंद्र ने वीर सावरकर के जीवन चरित्र का वाचन किया। सामूहिक गीत का अभ्यास हुआ जहां सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गीत का उद्घोष किया मुख्य शिक्षक एवं कार्यवाह महोदय ने सभी को संबोधित करते हुए बतलाया कि आज राष्ट्र की सेवा इंधन बचत करने के लिए है हम स्वयं भी बचत करें एवं लोगों को प्रेरित करें।

आरटीआई में जानकारी छिपाने पर राज्य सूचना आयोग सख्त

मझौली नगर परिषद को एक माह में 'दैनिक वेतन भोगियों' की जानकारी देने का आदेश, 3 साल पुराने मामले में गुण-दोष के आधार पर हुआ फैसला

मझौली, नवभारत, जबलपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)-2005 के तहत जानकारी देने में आनाकानी करने वाले स्थानीय निकायों और अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।

नगर परिषद मझौली में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती और उनके दस्तावेजों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने आदेश जारी करते हुए मझौली नगर परिषद को एक माह के भीतर अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज निःशुल्क प्रमाणित प्रति के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

क्या था पूरा मामला?

मिली जानकारी अनुसार मझौली के वार्ड क्रमांक 12 निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सुंदर लाल बर्मन ने 15 फरवरी 2023 को नगर परिषद मझौली में एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन के माध्यम से उन्होंने नगर परिषद में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती की नियमावली, उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां (सॉफ्टकॉपी में) और भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा की स्पष्ट जानकारी मांगी थी।

अधिकारियों का गैर-जिम्मेदाराना तर्क खारिज

मामला जब द्वितीय अपील के तहत राज्य सूचना आयोग पहुंचा, तो सुनवाई के दौरान मझौली नगर परिषद के सहायक लोक सूचना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सिंह राजपूत (सहायक राजस्व निरीक्षक) उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग के सामने तर्क दिया कि आवेदन 3 साल पुराना होने के कारण कार्यालय में इसके दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निकाय में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कोई भर्ती नहीं की गई है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कलेक्टर दर पर 'साप्ताहिक श्रमिक' रखे जाते हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैए और अजीबोगरीब तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट माना कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखने के संबंध में शासन की नियमावली की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जिससे विभाग पीछे भाग रहा है।

'थर्ड पार्टी' की निजता का रखा जाएगा ध्यान, आधार-बैंक डिटेल छिपेंगे

राज्य सूचना आयोग ने आदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को रेखांकित किया। आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि चाही गई जानकारी में यदि किसी कर्मचारी या तृतीय पक्ष के संवेदनशील व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर या अन्य निजी जानकारियां शामिल हैं, तो उन्हें अधिनियम की धारा 10 (पृथक्कीकरण का सिद्धांत) के तहत छुपा दिया जाए या हटा दिया जाए। इसके बाद शेष बची हुई प्रमाणित कॉपियां एक महीने के अंदर अपीलार्थी को बिना किसी शुल्क के सौंपी जाएं।

दस्तावेज नहीं होने पर देना होगा लिखित हलफनामा

राज्य सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में यह भी साफ किया है कि यदि वांछित जानकारी का कोई हिस्सा या अभिलेख कार्यालय में सचमुच उपलब्ध नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी को इसकी स्पष्ट और लिखित सूचना कारण सहित अपीलार्थी को देनी होगी। आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजकर प्रकरण को अंतिम रूप से निराकृत कर दिया गया है।

श्रीधर सोंधिया का निधन

नवभारत, जबलपुर। गेट नंबर 4 सांई बाबा मंदिर के पीछे रहने वाले श्रीधर सोंधिया का 59 की आयु में दुखद निधन हो गया है। आप सिद्धार्थ सोंधिया, वैष्णवी के पिता, भगवती सोंधिया के पति थे। अंतिम संस्कार रानीताल मुक्तिधाम किया गया।

वन कर्मियों से मारपीट करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

उमरिया। 24 मई को खेरवाटोला ग्राम पनपथा में घर के अन्दर बाघ के हमले में मौत पर उसी दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाने एवं घर के अन्दर घुसे बाघ के रेस्क्यू कार्यवाही के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए वन विभाग के शासकीय कर्मचारियों पर हमला कर शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए दंगा कारित किया गया। फरियादियों की रिपोर्ट पर थाना इंदवार में पृथक-पृथक कुल 3 अपराध दर्ज कर विवेचना में लिये गये।

बिजली-पानी व किसानों की बदहाली पर फूटा गुस्सा

मझौली के ग्राम पंचायत सिमरिया घाट में कांग्रेसियों ने फूंका मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला

मझौली, जबलपुर। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और किसानों की उपेक्षा को लेकर अब जनता और विपक्ष का सब्र का बांध टूट चुका है।

जिले के पाटन विस अंतर्गत आने वाली मझौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिमरिया घाट (सुनवानी ग्राम) में बिजली और पानी के गंभीर संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष संजय यादव के निर्देशानुसार आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आक्रोशित कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसके साथ ही, जल संकट इस कदर गहरा गया है कि ग्रामीणों को पानी के लिए मीलों भटकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री केवल कागजों और मंचों पर विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अन्नदाता परेशान है और गांवों में हाहाकार मचा है। सरकार की इस तानाशाही और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मंडलम अध्यक्ष नारायण सिंह (रिंकू) और पंचायत अध्यक्ष समरजीत राजपूत, रोहिणी राजपूत, सचिन राजपूत, छोटू महाराज, मीडिया प्रभारी विकास झरिया और अमित सेन के साथ मजल राजपूत, विजय दहिया, मुन्ना दहिया, प्रदीप दहिया, रज्जू दहिया, राजकुमार दहिया, नंदा सेन, सुरेश भूमिया, जितेंद्र बर्मन, शिवम सेन, शैलेश सिंह, रुपेश, ऋतिक, ओम, मोहित, अंशुल, दौलत, क्रिस, राज, सिवा, विवेक, आर्यन, जय, विशेष सहित सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

पुतला दहन के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग को दो टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह पुतला दहन तो महज एक शुरुआत है। यदि सिमरिया घाट, सुनवानी और आसपास के गांवों में बिजली की अघोषित कटौती तुरंत बंद नहीं की गई और पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, तो कांग्रेस पार्टी जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए बाध्य होगी।

मांग | भीषण गर्मी और हरे चारे के कमी से दूध उत्पादन घटा, सरकार से राहत प्रदान करने की मांग

पशु आहार की बढ़ती कीमतों से पशुपालकों की टूटी कमर

सिहोरा, नवभारत। सिहोरा तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है पशुपालकों द्वारा व्यवसाय की दृष्टि से गाय भैंस की डेरी खोलकर दुधारू पशुओ का पालन किया जा रहा है और इस महंगाई के युग में इन मवेशियों को खिलाने वाले पशु आहार चुनी चोकर खली पशु आहार चना चुनी छिलका व अन्य सामग्री की कीमतें निरंतर आसमान को छू रहीं हैं और वहीं दूसरी ओर इस भीषण गर्मी के दौर में दुग्ध उत्पादन गर्मी के चलते आधा हो गया ऐसे में पशुपालकों को इस व्यवसाय में लंबा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस और न तो सरकार और न ही पशुपालन विभाग ध्यान दे रहा है पशुपालकों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

पाशु पालकों ने बताया कि बैंक से पशु क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहे हैं वहीं पशुओं के लिए सुरक्षित चरनोई भूमि पर दबंगों के अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही ऐसे में मजबूरी में पशुपालकों को अपने पशुओं को दिन रात घर पर ही बांधकर खिलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई के दौर में पशु आहार की बढ़ती कीमतें जहां सुरसा की तरह आसमान को छू रहीं हैं वहीं दूसरी ओर पशुपालकों का दूध माटीमोल बिक रहा है गोसलपुर नगर में खुले निजी दूध कलेक्शन सेंटरो में पशु पालकों से गाय का दूध 40 रुपये और भैंस का दूध पचास से साठ रुपये लीटर खरीदा जा रहा है, दूध की कम कीमत मिलने के कारण पशुपालकों की लागत नहीं निकल रही है।

निजी दुग्ध संचालक मनमानी पर उतारू

पशुपालक रामदयाल दुबे, लक्ष्मी नारायण यादव, राम प्रकाश यादव, सूरज पटेल, अभिषेक चौरसिया, अमित जैन ने बताया कि मौजूदा स्थिति में पशुपालन घाटे का सौदा साबित हो रहा है सरकार के द्वारा भूसा दाना व अन्य किसी भी सामग्री में सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती वहीं दूसरी ओर गोसलपुर क्षेत्र में सरकारी दूध संकलन केंद्र न होने के कारण निजी दूध संकलन केंद्र के संचालक औने पौने दाम पर दूध खरीद रहे हैं और तो और पशुपालकों ने यह भी बताया की पशुओं को होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए निःशुल्क मिलने वाली दवाइयां वेटरनरी अस्पतालों न होने से मजबूरी में पशुपालकों को निजी दवाई दुकानों से महंगी

पशुओं के लिए दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं

पशु पालकों ने बताया कि दाना भूसा महंगा है अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं की अगर ऐसी माटी मोल दूध बिकता रहा तो पशुपालकों को इस व्यवसाय से कैसे मुनाफा हो पाएगा जहां एक और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करते हैं वही दूसरी ओर पशुपालक को दूध का सही दाम भी नहीं मिल पा रहा है दूसरी ओर पशुओं की सुरक्षित भूमि से अतिक्रमण नहीं अलग हो पा रहा है ऐसे में पशुपालन को कैसे बढ़ावा मिलेगा निरंतर दुग्ध उत्पादन क्षमता घट रही है, वहीं पशुओं के बीमार होने पर दवाईयां भी उन्हें खरीदनी पड़ती है। पशुपालको ने इस संबंध में जिला प्रशासन के मुखिया से ध्यान देने की मांग की है।